बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 224 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 23 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पहले टक्कर मारी, फिर पैरों पर चढ़ाई कार - दिल्ली में लड़की ने सिपाही को कुचला, बिना लाइसेंस कैसे मिली गाड़ी?

नई दिल्ली। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बिना लाइसेंस की कार चला रही एक युवती ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को कुचल दिया। नांगलोई के रहने वाला सिपाही जितेंद्र कुमार घटना के समय बाइक से थाने जा रहे थे। दोनों पैर पर कार का पहिया चढ़ने से वह बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने उसे पास के दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया। कार चला रही युवती की पहचान 19 साल की ओशिन गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 28 साल का जितेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ नांगलोई इलाके में रहते हैं।

पुलिस पर आधार और पैन कार्ड मांगने का आरोप, सीजेपी-पुलिस में विवाद; कॉकरोचों को मिला किसानों का साथ

नई दिल्ली। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का धरना प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को भी बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। सीजेपी के धरने के तीसरे दिन आधार कार्ड और पैन कार्ड जांच को लेकर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पुलिस के बीच बहस देखने को मिली। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि धरना स्थल पर आने वाले लोगों से आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे जा रहे हैं, जबकि वह केवल प्रदर्शन में शामिल होने, पानी पहुंचाने या भोजन देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला है और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों की निजी जानकारी क्यों ली जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड देखकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जा सकती है और यह लोगों की निजता से जुड़ा विषय है।

हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर सभी आरोपों को निराधार बताया। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के चढ़ूनी गुट ने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी धड़े ने प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगे भी रखने का फैसला किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश भर के किसानों और मजदूरों से जंतर मंतर पर आकर छात्रों का समर्थन करने की अपील की थी, जिसके जवाब में बीकेयू (चढ़ूनी) ने छात्रों के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने पर अभिजीप दीपके ने बताया कि मैं भारतीय किसान यूनियन का हमारे आंदोलन का समर्थन करने और छात्रों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने भी इसकी सराहना की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, किसानों का यह फैसला अच्छा है। जब तक सरकार हमारी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के लिए चाय, समोसे और पानी की व्यवस्था की गई है। कई स्वयंसेवक लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, यह केवल मंच से भाषण देने का आंदोलन नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के सहयोग और समर्पण का परिणाम है। मंच से कुछ स्वयंसेवकों का जिक्र भी किया गया, जो अपनी नौकरी और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ साथ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि ऐसे कार्यकर्ता आंदोलन की रीढ़ हैं, जो बिना किसी प्रचार प्रसार के लगातार सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी जन आंदोलन की वास्तविक ताकत वह लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर व्यवस्थाओं को संभालते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन की सफलता सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है।

ऑपरेशन कीचड़ से क्या संविधान बदलना चाहती है बीजेपी? पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने सोमवार को महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के तहत दल-बदल की चर्चा को ऑपरेशन कीचड़ करार दिया और शिवसेना में हुई बगावत को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। बात करते हुए पवन खेड़ा ने बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी सांसदों को चुराने का काम कर रही है। खेड़ा ने कहा कि यह ऑपरेशन कीचड़ है क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कमल नहीं खिल सका, लेकिन हमारा सवाल यह है कि वे (पीएम नरेंद्र मोदी) इस बात से इतने आहत क्यों हैं कि वे 400 के बजाय 240 सीटों पर ही रुक गए, कि अब वे भ्रष्ट और शिवसेना जैसी दूसरी पार्टियों से सांसदों को चुराने में लगे हैं? क्यों? इरादा क्या है? क्या असल में संविधान बदलना चाहते हैं? इस डकैती के पीछे क्या मकसद है? ऐसा तब हुआ जब 18 जून को सेना (यूबीटी) के छह सांसदों ने विद्रोह कर दिया और संसदीय दल की बैठक में भाग नहीं लिया। यवतमाल-वाशिम के सांसद संजय देशमुख, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर, परभणी के सांसद संजय जाधव, शिरडी के सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे, मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल और उस्मानाबाद के सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर वे थे जो सेना (यूबीटी) संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की संभावना है। आज इससे पहले, आदित्य ठाकरे ने बागी नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बजाय निजी लालच को प्राथमिकता दी। एक्स पर एक पोस्ट में, ठाकरे ने दावा किया कि कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी के समर्थन से चुने गए इन विधायकों ने उन विचारधाराओं को छोड़ दिया है, जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें वोट मिला था।

सरकार ने ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों में हेरफेर की - कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण मजदूरी में बड़ी वृद्धि दर्शाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि आंकड़ों में हेराफेरी करना ही उसका एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। रमेश का कहना है कि जून, 2025 से मार्च, 2026 के बीच रिपोर्ट की गई वार्षिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि लगभग छह प्रतिशत से बढ़कर 17-18 प्रतिशत दिखाई गई, जबकि औसत दैनिक मजदूरी केवल एक महीने में 12.7 प्रतिशत बढ़ी हुई दर्ज की गई। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, वर्ष 2024 में हमने यह मुद्दा उठाया था कि मोदी सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से रोजगार की परिभाषा बदलकर रोजगार सृजन में भारी उछाल का दावा किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018 के बाद से 16.8 करोड़ नए रोजगार सृजित होने का दावा किया।

बाद में, इस प्रयास में भूमिका निभाने वाले रिजर्व बैंक के शीर्ष नेतृत्व को मोदी सरकार में महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया। उन्होंने दावा किया कि अब मोदी सरकार ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों के साथ भी यही करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता का कहना है, हम लगातार यह कहते रहे हैं कि भारत की आर्थिक सुस्ती का मूल कारण वास्तविक (महंगाई-समायोजित) मजदूरी में ठहराव है, जिसने उपभोग वृद्धि को कमजोर किया है और निजी निवेश को हतोत्साहित किया है। इस मूल समस्या का समाधान करने में असफल रहने के बाद, अब सरकार ग्रामीण मजदूरी में कृत्रिम उछाल दिखाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कथित मजदूरी वृद्धि वास्तव में एक कार्यप्रणाली में बदलाव का परिणाम है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, वास्तविकता यह है कि मजदूरी के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तविक वार्षिक मजदूरी वृद्धि लगभग 4.3 प्रतिशत ही होती, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कमजोर वृद्धि होती। रमेश ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यही आंकड़ों में हेरफेर (डेटा डॉक्टरिंग) का एंटायर पॉलिटिकल साइंस है।

तुम निकम्मे लोग, यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं होती, डीके शिवकुमार के समर्थकों पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पार्टी कार्यकर्ताओं की आलोचना की, जिन्होंने पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह में कामकाज में बाधा डाली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में डीके-डीके के नारों से साफ़ तौर पर नाराज़ होकर, वरिष्ठ नेता ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। उन्होंने उन्हें बेकार लोग कहा और याद दिलाया कि यह कार्यक्रम पार्टी का था, न कि किसी एक नेता पर केंद्रित। खड़गे ने तेवर दिखाते हुए कहा कि चुप हो जाओ! बैठ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश तुम्हारे हाथ में आ गया हो। बेकार लोग! इस हंगामे के एक वीडियो में शिवकुमार भीड़ को शांत करने की कोशिश करते दिखे; मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने लोगों से चुपचाप बैठने का इशारा किया। खड़गे ने आगे कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की बैठक है।

यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी लोग पार्टी को मज़बूत और एकजुट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर एक व्यक्ति एक नाम चिल्लाता रहे और दूसरा कोई और नाम, तो क्या बाकी लोग यहाँ सिर्फ़ कचरा साफ़ करने आए हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रसाद ने रविवार को एक अधिवेशन में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने पार्टी का झंडा सौंपकर हरिप्रसाद को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी। शिवकुमार ने 2020 से अब तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

कैग ऑडिट नोटिस रद करने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज, अदालत ने क्यों ठुकराई बीएसईएस की मांग?

नई दिल्ली। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) के भेजे गए ऑडिट नोटिस को चुनौती देने वाली बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल कैग की ओर से सिर्फ एक नोटिस ही जारी किया गया है और ऑडिट की असल और औपचारिक प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में इस स्तर पर नोटिस को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट पर किसी भी तरह की कोई रोक या पाबंदी नहीं है। हालांकि, अदालत ने निर्देश भी दिया है कि इस ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से और कड़ाई से पालन किया जाना बेहद जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आगे चलकर कंपनी को ऑडिट की प्रक्रिया या किसी और पहलू पर आपत्ति होती है, तो वह इसे उचित मंच पर चुनौती दे सकती है। बीएसईएस ने नोटिस को चुनौती देते हुए इसे गैर-कानूनी और अधिकार का गलत इस्तेमाल बताया। बीएसईएस ने तर्क दिया था कि अदालतों के फैसलों के खिलाफ जारी किया गया नोटिस रद कर दिया जाना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज

नई दिल्ली।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के दावों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे रामलला के दर्शन करने जाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी थी कि आगामी शुक्रवार (26 जून) को वे अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्रीराम के दर्शन करेंगे. अब दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मामले पर केजरीवाल पर तंज कसा है. अरविंद केजरीवाल के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा शुक्रवार को जाएंगे? जुमे की नमाज के पहले या उसके बाद? कपिल मिश्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया था कि वह राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से बेहद दुखी हैं. हर सनातनी दुखी है. इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि शुक्रवार को रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे. समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले दावा किया था कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में गबन हो रहा है. इसके बाद बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा था. मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर कथित चंदा चोरी में जांच के निर्देश दिए थे. एसआईटी जल्द ही जांच के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी को पेश कर सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों के बीच लखनऊ के एक जौहरी ने दावा किया कि उन्हें मंदिर को दान में दिए गए तीन किलोग्राम वजनी चांदी के दीपक और चांदी की अन्य वस्तुओं की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि चांदी को विधिवत पूजा के बाद ट्रस्ट कार्यालय में सौंपा गया था और इसकी रसीद भी दी गई थी, हालांकि तीन किलो चांदी की कोई रसीद उन्हें नहीं मिली. उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि भूमिपूजन के दौरान यह सामग्री स्थापित नहीं की गई. संभवतः प्रोटोकॉल कारणों से ऐसा हुआ होगा.

ग्रेट निकोबार परियोजना पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल, केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में जयराम रमेश ने परियोजना के तहत बनने वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास को लेकर कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। पत्र में जयराम रमेश ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास के लिए निजी कंपनी की भागीदारी के लिए निविदाएं जारी करने की समय-सीमा और निजी कंपनी के चयन की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। उन्होंने यह भी पूछा कि परियोजना में निजी क्षेत्र की न्यूनतम हिस्सेदारी 55 प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो क्या 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी, या फिर सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी न्यूनतम हिस्सेदारी तय की गई है? जयराम रमेश ने प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता भी जताई। कांग्रेस नेता ने कहा कि समिति के रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में कम से कम 55 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली इकाई के पास होनी चाहिए। क्या 55 प्रतिशत न्यूनतम निजी हिस्सेदारी का मतलब है कि परियोजना में 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी? क्या बंदरगाह क्षेत्र में स्वामित्व का विविधीकरण सुनिश्चित किया जाएगा या फिर हवाईअड्डों की तरह ऐसी स्थिति बनने दी जाएगी, जहां एक ही निजी कंपनी अधिकांश परिसंपत्तियां हासिल कर ले? जब पीपीपीएसी ने परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो क्या मंत्रालय अपने बजट से पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराएगा? रमेश ने मंत्री से यह भी आग्रह किया कि वे निविदा जारी करने और निजी भागीदार के अंतिम चयन की संभावित समय-सीमा साझा करें। जयराम रमेश इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी कई पत्र लिख चुके हैं। इन पत्रों में उन्होंने परियोजना से होने वाले संभावित पर्यावरणीय विनाश और पारिस्थितिकीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। हाल ही में उन्होंने पर्यावरण मंत्री यादव को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर्याप्त नहीं हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। कांग्रेस का आरोप है कि गलाथिया बे में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से बड़े पैमाने पर प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचेगा और इससे गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा होगा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह दावा कि परियोजना का उद्देश्य रखा और ट्रांसशिपमेंट अवसंरचना का विकास है, जबकि यह भ्रामक है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस परियोजना का असल उद्देश्य एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाना है ताकि वह देश की सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकीय भूमि पर होटल और कैसीनो विकसित कर सके। ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ एक नागरिक-सह-नौसैनिक हवाईअड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र विकसित करने की भी योजना है।

सम्पादकीय...

शक्ति का नया अध्याय

भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए 21 जून 2026 को तीन स्वदेश निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना को समर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित एक विशेष समारोह में अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरी, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अभय तथा विशाल सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया। यह केवल तीन नए जहाजों का नौसेना में प्रवेश नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमता, समुद्री रणनीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का प्रतीक भी है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब केवल हथियारों और रक्षा उपकरणों का खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि निर्माता और निर्यातकर्ता दोनों बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसकी समुद्री क्षमता से गहराई से जुड़ी होती है। उनका यह वक्तव्य भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना में 40 से अधिक स्वदेश निर्मित युद्धपोतों और पनडुब्बियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार द्वारा घोषित 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज केवल आर्थिक निवेश नहीं, बल्कि भारत के समुद्री भविष्य और औद्योगिक विस्तार में निवेश है। इन तीनों जहाजों में सबसे अधिक चर्चा आईएनएस दुनागिरी की हो रही है। यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत निर्मित नीलगिरि श्रेणी का पांचवां स्टील्थ फ्रिगेट है और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इस श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। दुनागिरी का नाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिमालयी पर्वत शिखर से प्रेरित है, जो भारतीय परंपरा और सैन्य गौरव दोनों का प्रतीक है। आईएनएस दुनागिरी आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है। इसमें आठ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं, जो दुश्मन के समुद्री और स्थलीय लक्ष्यों को अत्यधिक सटीकता के साथ नष्ट करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त बराक-8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली इसे हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी स्टील्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है, जिससे यह आधुनिक नौसैनिक युद्ध में बेहद प्रभावशाली बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जहाज आईएनएस अभय है, जिसे विशेष रूप से पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे -सबमरीन हंटर- भी कहा जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य देशों की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों को देखते हुए इस प्रकार के जहाजों का महत्व और बढ़ जाता है। आईएनएस अभय में अत्याधुनिक सोनार प्रणाली, टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन रॉकेट लगाए गए हैं। यह जहाज उथले समुद्री क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। भारत की लंबी समुद्री सीमा और तटीय सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए यह पोत नौसेना की परिचालन क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा। तीसरा पोत आईएनएस संशोधक है, जो एक विशाल सर्वेक्षण पोत है। यद्यपि यह पारंपरिक युद्धपोत नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता किसी भी सैन्य और आर्थिक रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जहाज आधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय अध्ययन प्रणालियों से सुसज्जित है। आईएनएस संशोधक समुद्र की गहराई, समुद्री धाराओं, समुद्र तल की संरचना और तटीय क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करने में सक्षम है। इसके साथ चार विशेष सर्वेक्षण मोटरबोट भी तैनात हैं। यह पोत न केवल नौसैनिक अभियानों में सहायता करेगा, बल्कि समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, तटीय विकास, बंदरगाह निर्माण और अपतटीय परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा। भारत की समुद्री रणनीति में इन जहाजों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है। चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना केवल देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इन जहाजों के शामिल होने को भारत के मजबूत रक्षा विनिर्माण तंत्र और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रमाण बताया। उनका कहना है कि देश अब रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम कर रहा है और वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन युद्धपोतों का निर्माण भारतीय उद्योग, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और हजारों कुशल श्रमिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। इससे न केवल देश की रक्षा क्षमता मजबूत हुई है, बल्कि रोजगार, तकनीकी विकास और औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति भी है। अंततः आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस अभय और आईएनएस संशोधक का भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री शक्ति के नए युग की शुरुआत का संकेत है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और युद्धपोतों का निर्माता भी बन रहा है। आने वाले वर्षों में ये तीनों पोत भारतीय नौसेना की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेंगे। भारत की समुद्री शक्ति का यह विस्तार न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। निर्माता से निर्णयकर्ता- बनने की प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना इन जहाजों के माध्यम से वास्तविकता का रूप लेती दिखाई दे रही है।

उत्तराखंड के गुरुद्वारे में निहंगों का हंगामा- आस्था, कानून और संवाद की परीक्षा

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नागरासू गुरुद्वारे में जून 2026 में हुई एक घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हथियारों से लैस निहंग सिखों के एक समूह ने गुरुद्वारे में घुसकर हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक सिख श्रद्धालु को बंधक बनाकर छत पर ले गए। उनकी मांग थी कि चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुई झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए उनके चार साथियों को रिहा किया जाए। यह घटना केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक पहचान, सामुदायिक नेतृत्व और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन की चुनौती भी प्रस्तुत करती है। घटना की शुरुआत 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार में हुई एक झड़प से जुड़ी है। बताया गया कि श्री हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। प्रारंभिक बहस जल्द ही हिंसक संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि कुछ निहंगों ने तलवारों से हमला किया, जिससे चार स्थानीय लोग घायल हो गए। इस झड़प में एक निहंग भी घायल हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मोहाली, पंजाब के चार निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद निहंग समुदाय के कुछ सदस्यों ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। इसी सिलसिले में वे रुद्रप्रयाग जिले के नागरासू गुरुद्वारे पहुंचे। बदरीनाथ हाईवे पर स्थित यह गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जाने और लौटने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधन के अनुसार, निहंगों ने मांग की कि आगामी विरोध प्रदर्शन के लिए आने वाले लोगों के ठहरने हेतु 50 से 60 कमरों की व्यवस्था की जाए। जब प्रबंधन इतनी बड़ी व्यवस्था करने में असमर्थ रहा, तब स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि निहंगों ने गुरुद्वारे में हंगामा किया, तीसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद एक बुजुर्ग सिख श्रद्धालु को बंधक बना लिया। पुलिस के अनुसार, समूह के सदस्य भाले, तलवारें, कुल्हाड़ियां और कृपाण जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने तीसरी मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और छत से नारेबाजी शुरू कर दी। इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को संभालने में संयम का परिचय दिया। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने कहा कि पुलिस, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन लगातार निहंगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य बल प्रयोग के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान निकालना था। यह रणनीति आंशिक रूप से सफल भी रही, क्योंकि बातचीत के दौरान एक निहंग छत से नीचे आया और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यह गुरुद्वारे के भीतर का विवाद है और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गुरुद्वारे में अरदास, लंगर और अन्य धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहीं। यह घटना निहंग परंपरा को लेकर भी चर्चा का विषय बनी है। निहंग सिख परंपरा में योद्धा समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। उनका इतिहास सिख धर्म की सैन्य परंपराओं से जुड़ा हुआ है। वे अक्सर पारंपरिक नीले वस्त्र पहनते हैं और अपने साथ धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के हथियार रखते हैं। सिख इतिहास में निहंगों ने धर्म और समुदाय की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कानून और संवैधानिक दायरे में होना आवश्यक है। चाहे किसी समुदाय की शिकायत कितनी भी गंभीर क्यों न हो, हिंसा, बंधक बनाना या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इस घटना ने धार्मिक अधिकारों और कानूनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को लेकर बहस को जन्म दिया है। दूसरी ओर, यह भी आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले में निष्पक्ष जांच हो। यदि किसी समुदाय को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्णप्रयाग झड़प की जांच के आदेश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्पक्ष जांच से न केवल सच्चाई सामने आएगी, बल्कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी और असंतोष को भी कम किया जा सकेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे सकारात्मक पहलू प्रशासन द्वारा अपनाई गई संवाद की नीति रही। ऐसे संवेदनशील मामलों में बल प्रयोग कई बार स्थिति को और अधिक जटिल बना सकता है। पुलिस और प्रशासन ने धैर्य, बातचीत और विश्वास निर्माण के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे किसी बड़े टकराव की संभावना कम हुई। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि धार्मिक स्थलों का मूल उद्देश्य शांति, सेवा और आध्यात्मिकता है। गुरुद्वारे विशेष रूप से सेवा, समानता और भाईचारे के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे स्थानों का किसी भी प्रकार के संघर्ष या हिंसक प्रदर्शन का केंद्र बनना चिंताजनक है। धार्मिक संस्थानों और समुदायों की जिम्मेदारी है कि वे संवाद और शांति के मूल्यों को प्राथमिकता दें। अंततः रुद्रप्रयाग का यह घटनाक्रम केवल एक स्थानीय विवाद नहीं है। यह दिखाता है कि जब भावनाएं, पहचान और न्याय की मांग एक साथ जुड़ जाती हैं, तब स्थिति कितनी संवेदनशील हो सकती है। ऐसे समय में प्रशासन, धार्मिक नेतृत्व और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष और प्रशासनिक कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में संवाद, कानून का सम्मान और शांतिपूर्ण समाधान ही स्थायी रास्ता हो सकता है। उत्तराखंड की यह घटना इसी महत्वपूर्ण सीख की याद दिलाती है।

बदनाम न करो

अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मन्दिर में चढ़ावे की कथित चोरी या घपले की खबर नितान्त पीड़ादायक है क्योंकि भगवान श्री राम से भारत व विश्व के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था व श्रद्धा जुड़ी हुई है। श्री राम का मर्यादित आदर्श मनुष्य चरित्र भारतीयों के लिए अनुकरणीय इस तरह रहा है कि हर घर में रामायण का होना निश्चित होना माना जाता है और किसी भी विवाह में इसकी प्रति भेंट करना सबसे अमूल्य उपहार होती है। इसलिए स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी जनजीवन में व्याप्त राम के प्रति अगाध सम्मान को संज्ञान में लेते हुए रामराज्य की परिकल्पना का चित्रण स्वतन्त्र भारत के लिए किया और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीयों की सहिष्णुता व एकता का परिचायक बना दिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि गांधी जानते थे कि स्वतन्त्रता आन्दोलन से आम जनता को जोड़ने के लिए उसके आदर्श प्रतीक ही पूरे समाज में नव ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। अतः श्री राम भारत की उस आत्मा में समाये हुए हैं जिसे भारतीयता भी कहते हैं। इसलिए उनके मन्दिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में यदि हेर-फेर की सूचना आती है तो इससे समूचे भारत की सांस्कृतिक पहचान पर गहरी चोट पहुंचती है। हालांकि महात्मा गांधी की कुछ क्षेत्रों में इस बात को लेकर आलोचना भी हुई कि उन्होंने हिन्दू प्रतीकों को ही क्यों चुना मगर गांधी ने इसका उत्तर सर्वत्र रामराज्य परिकल्पना से ही दिया परन्तु स्वतन्त्र भारत में जिस तरह अयोध्या में 80 व 90 के दशक में राम मन्दिर निर्माण आन्दोलन चला उसने भारतीय राजनीति को ही आमूल-चूल रूप से बदल कर रख दिया और इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय आकार ले लिया जिसमें हिन्दू समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अपनी आहुती दी और यह नारा बुलन्द किया कि 'मन्दिर वहीं बनायेंगे, जहां राम का जन्म हुआ था'। तब हमने देखा कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर 16वीं सदी में खड़ी की गई बाबरी मस्जिद किस तरह ढहा दी गई और बाद में इसका मुकदमा स्थानीय न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और वहां से विवादित स्थान हिन्दू समुदाय को मन्दिर निर्माण के लिए दिया गया। लगभग पांच सौ साल के लम्बे संघर्ष के बाद भारत के हिन्दुओं को अयोध्या का वह स्थल मिला जिसे वे मानते थे कि वहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग शहीद भी हुए मगर उनकी आस्था नहीं डिगी और वे मानते रहे कि भारत में मुस्लिम आक्रान्ताओं ने उस दौर में भारत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए हिन्दू धर्म के आस्था केन्द्रों की पहचान बदली और उनका इस्लामीकरण किया। बाबरी मस्जिद को तब आन्दोलनकारी नेताओं ने गुलामी का प्रतीक बताया और उससे आजादी पाने का अभियान शुरू किया, तब जाकर अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण एक ट्रस्ट गठित करके किया गया। मन्दिर निर्माण के बाद ट्रस्ट का पुनर्गठन हुआ और इसकी देखरेख का जिम्मा इसे सौंप दिया गया, जिसमें श्री राम पर चढ़ने वाले चढ़ावे का हिसाब-किताब रखने के लिए अलग से प्रभाग था। मगर मन्दिर प्रबन्धन की तरफ से इसमें ढीलढाल बरती गई जिसकी वजह से चढ़ावे की धनराशि व कीमती वस्तुओं की चोरी किये जाने का कथित मामला प्रकाश में आया है। वास्तव में यदि ऐसा हुआ है तो यह ऐसा कुकृत्य है जिसे किसी भी स्तर पर क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि मन्दिर में एक गरीब मजदूर भी अपने खून-पसीने की कमाई में से ही कुछ अंश का दान करता है। इसलिए चढ़ावे में चोरी होने की घटना पूरे भारत और इसकी संस्कृति का घोर निरादर है जिसके लिए दोषी किसी भी रूप में बख्शे नहीं जाने चाहिए।

इवान सेपेदा- संघर्ष, न्याय और बदलाव की राजनीति के बीच कोलंबिया का नया चेहरा

कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव 2026 में एक ऐसा नाम सबसे अधिक चर्चा में है, जिसने कभी स्वयं को राष्ट्रपति पद का दावेदार नहीं माना था। 63 वर्षीय सीनेटर इवान सेपेदा आज देश के सबसे प्रभावशाली वामपंथी नेता के रूप में उभरे हैं और राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। शांत स्वभाव, संयमित भाषा और एक शिक्षक जैसी सादगीपूर्ण छवि वाले सेपेदा की राजनीतिक यात्रा केवल चुनावी राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय, मानवाधिकार और दशकों पुराने सशस्त्र संघर्ष के खिलाफ लड़ाई की कहानी भी है। बोगोटा में जून 2026 की एक चुनावी रैली में जब युवा समर्थक -सेपेदा प्रेसिडेंटे- के नारे लगा रहे थे, तब यह स्पष्ट हो गया था कि वह केवल एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि कोलंबिया के वामपंथी आंदोलन की नई उम्मीद बन चुके हैं। हालांकि एक वर्ष पहले तक स्वयं सेपेदा राष्ट्रपति बनने को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं मानते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राष्ट्रपति पद अत्यंत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने कभी गंभीरता से इस पद के लिए नहीं सोचा था। लेकिन राजनीति कभी-कभी परिस्थितियों से दिशा तय करती है। सेपेदा का जीवन भी इसी का उदाहरण है। उनकी पूरी राजनीतिक पहचान कोलंबिया के छह दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष और उससे जुड़े मानवाधिकार प्रश्नों से निर्मित हुई है। इवान सेपेदा का जन्म ऐसे दौर में हुआ जब कोलंबिया गृह संघर्ष, वैचारिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। उनके पिता मैनुअल सेपेदा और माता यिरा कास्त्रो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उनके पिता राजनीतिक समाधान और शांति वार्ता के समर्थक थे। 1980 के दशक में जब कोलंबियाई सरकार और वामपंथी विद्रोही संगठन एफएआरसी के बीच शांति प्रक्रिया शुरू हुई, तब पैट्रियोटिक यूनियन नामक एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। मैनुअल सेपेदा इसी दल से सीनेटर चुने गए। लेकिन 1994 में संसद पहुंचने के एक वर्ष के भीतर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में अनेक रिपोर्टों में आरोप लगाए गए कि इस हत्या में अर्धसैनिक समूहों और राज्य एजेंसियों की भूमिका थी। अपने पिता की हत्या ने इवान सेपेदा के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने और संघर्ष के पीड़ितों की आवाज बनने का संकल्प लिया। यही संकल्प आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान का आधार बना। मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में वर्षों तक काम करने के बाद सेपेदा 2010 में संसद पहुंचे। अपने पहले ही दिन वे संसद में बाल्टी और पोछा लेकर पहुंचे थे। उनका संदेश स्पष्ट था–वह भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधों से दागदार व्यवस्था को साफ करना चाहते हैं। संसद में उनका सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे के साथ रहा। उरीबे को कोलंबिया के दक्षिणपंथी राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। सेपेदा ने उन पर अर्धसैनिक समूहों और मादक पदार्थ तस्करों से संबंध रखने के आरोप लगाए। दोनों नेताओं के बीच वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली। 2025 में उरीबे को रिश्वत और गवाहों को प्रभावित करने के मामले में दोषी ठहराया गया, हालांकि बाद में फैसला पलट दिया गया। इसके बावजूद इस मुकदमे ने सेपेदा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वामपंथी राजनीति में वह एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए जिसने देश के सबसे शक्तिशाली दक्षिणपंथी नेता को अदालत तक पहुंचाया। इसी पृष्ठभूमि में वह राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में आए और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की पार्टी हिस्टोरिक पैक्ट के उम्मीदवार बने। पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय, भूमि सुधार तथा असमानता कम करने की नीतियों को बढ़ावा दिया। सेपेदा ने अपने चुनाव अभियान में इन नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। उनका कहना है कि पेट्रो द्वारा शुरू किए गए सुधारों को केवल जारी ही नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें और व्यापक बनाया जाएगा। कृषि सुधार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और आर्थिक असमानता कम करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हालांकि चुनावी मुकाबला उनके लिए आसान नहीं है। रन-ऑफ चुनाव में उनका मुकाबला दक्षिणपंथी उम्मीदवार से है। आपराधिक मामलों के वकील रहे डे ला एस्प्रिएला कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं।

उन्होंने अपराध और विद्रोही हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई का वादा किया है। पहले दौर के मतदान में डे ला एस्प्रिएला को लगभग 43 प्रतिशत वोट मिले थे और वह सबसे आगे रहे। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण सुरक्षा को लेकर जनता की चिंता है। पिछले कुछ वर्षों में कोलंबिया में हिंसा और सशस्त्र समूहों की गतिविधियां फिर बढ़ी हैं, जिससे मतदाताओं के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। यही मुद्दा सेपेदा की सबसे बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने राष्ट्रपति पेट्रो की टोटल पीस नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस नीति का उद्देश्य विद्रोही संगठनों और आपराधिक समूहों के साथ बातचीत के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित करना था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह रणनीति अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। कई सशस्त्र समूहों ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और देश के कुछ हिस्सों में हिंसा बढ़ गई। इस कारण विपक्ष ने सेपेदा को सीधे तौर पर सुरक्षा विफलताओं से जोड़ना शुरू कर दिया। चुनाव के दूसरे चरण में पहुंचने के बाद सेपेदा ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने माना है कि -टोटल पीस- नीति में कई कमियां थीं और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि वे उन सशस्त्र संगठनों से बातचीत नहीं करेंगे जो नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं। इसके अलावा उन्होंने संविधान में बड़े बदलावों की उस विवादास्पद योजना से भी दूरी बना ली है, जिसे राष्ट्रपति पेट्रो आगे बढ़ा रहे थे। यह कदम मध्यमार्गी और अनिर्णीत मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सेपेदा के लिए चुनाव जीतना कठिन होगा। दक्षिणपंथी दलों का बड़ा हिस्सा डे ला एस्प्रिएला के पीछे एकजुट हो चुका है। दूसरी ओर, कई मध्यमार्गी नेता अब तक किसी एक उम्मीदवार का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि सेपेदा की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी संगठन और वामपंथी समर्थकों का मजबूत नेटवर्क है। ग्रामीण क्षेत्रों और बड़े शहरों के श्रमिक वर्ग में उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त है। यदि मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो वे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। अंततः इवान सेपेदा का चुनाव अभियान केवल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह कोलंबिया की दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टियों के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है। एक ओर सामाजिक न्याय, शांति वार्ता और सुधारों का एजेंडा है, तो दूसरी ओर सुरक्षा, कठोर प्रशासन और पारंपरिक व्यवस्था की वापसी की मांग। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, इवान सेपेदा पहले ही कोलंबिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। अपने पिता की हत्या से शुरू हुई न्याय की लड़ाई उन्हें देश के सर्वोच्च पद की दहलीज तक ले आई है। अब देखना यह है कि क्या यह संघर्ष उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा पाता है या नहीं।

हिंदू नैतिकता, संघ और भारतीय समाज

पिछले दिनों स्वयं सेवी संगठनों के कुछ मित्रों के आमंत्रण पर जयपुर में था। वह गोष्ठी सामाजिक नागरिक संस्थाओं के आत्मावलोकन की एक कोशिश थी।लेकिन इस आत्मावलोकन में आत्मविश्वास और अभय नदारद था। वहां सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भीतर एक किस्म का भय था और नियम कानून का पूरी तरह से पालन करने के बावजूद उन्हें निरंतर यह भय सता रहा था कि कब समाज उनके काम को नष्ट कर देगा या कब सरकार के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े स्वयं सेवी संगठन(प्रधानमंत्री की लाल किले से की गई घोषणा के अनुसार) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अतिरिक्त आत्मविश्वास या दर्प के साथ देश की संवैधानिक, नैतिक और कानून व्यवस्था को चुनौती देता रहता है और उसे कोई खौफ होने के बजाय उल्टे समाज और दूसरे नागरिक संगठनों को उससे खौफ है। यह खौफ स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बीजापुर से चुने गए दलित सांसद रमेश जिगजिनागी ने कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियंक खड़गे को एक सीख देते हुए व्यक्त किया है। प्रियंक खड़गे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या आप के संगठन का पंजीकरण है क्योंकि आप का संगठन सौ साल पूरा कर चुका है, वह प्रदेश में बहुत सारी गतिविधियां करता रहता है और आप ने दावा भी किया है जब जरूरत पड़ी तो आप का संगठन तीन घंटे में सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनाती कर सकता है। उनके सवालों में यह भाव छुपा है कि आखिर आप के संगठन का पंजीयन क्यों नहीं है और क्या वह कोई मिलिशिया या सैन्य संगठन है जो देश की सुरक्षा का दावा कर रहा है। प्रियंक खड़गे के पत्र पर संघ के पदाधिकारी और वकील आक्रामक ढंग से टूट पड़े हैं और कह रहे हैं कि क्या हिंदू समाज का पंजीयन है। अगर हिंदू समाज का पंजीयन नहीं है तो संघ को पंजीयन कराने की क्या आवश्यकता है। जाहिर सी बात है इस तर्क का विस्तार किया जाए तो बहुत सारे संगठनों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। इससे देश में एक किस्म की अराजकता पैदा होगी। लेकिन वैसी ही अराजकता भरी चेतावनी जिगजिनागी महोदय ने दी है। उनकी चेतावनी में जातिगत पूर्वाग्रह तो है ही साथ में एक फासीवादी धमकी भी है। उनका कहना है कि एक दलित को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर सवाल उठाने की आवश्यकता क्या है। फिर एक गृहमंत्री के पास दूसरे काम नहीं है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन उनकी आखिरी बात और भी भयानक है। उनका कहना है कि जिसने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर सवाल उठाए वह बच नहीं पाया। उनका यह कथन एक हद तक राष्ट्रीय स्तर पर सही हो सकता है तो कर्नाटक के स्तर पर अधिक सही है। कर्नाटक में पत्रकार गौरी लंकेश, साहित्यकार एम.एम कलिबुर्गी और महाराष्ट्र में अंधविश्वास के विरुद्ध अलख जगाने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्याएं इस बात का प्रमाण है। इस बीच अयोध्या के श्रीरामजन्मभूमि के मंदिर में चंदा चोरी का मसला भी संघ परिवार की नैतिकता को चुनौती दे रहा है। संघ परिवार जो अपने को समस्त हिंदू धर्म का रहनुमा और संरक्षक बताता है वह काफी संघर्षों के बाद बने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की दानराशि को न तो रखवाली कर पाया न ही उसमें पारदर्शिता कायम करने की जरूरत मानता है। एक तरफ एसआईटी बनाकर अपने दायित्वों की इतिश्री मान लेने वाले और महीने में चार बार अयोध्या का दौरा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो विपक्षी नेता अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे मारीच हैं, खर दूषण हैं और रावण हैं। जबकि ट्रस्ट के अहम पदाधिकारी नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि यह तो डकैती है और किसी भी तरह से वह मामला पंद्रह दिन में उजागर नहीं होने वाला है।

संघ परिवार के तर्क वितर्क और कुतर्क और गतिविधियों ने न सिर्फ संवैधानिक नैतिकता को सवालिया घेरे में ला दिया है बल्कि हिंदू नैतिकता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने गुरु और अमेरिकी दार्शनिक जान डेवी से प्रेरणा लेते हुए संवैधानिक नैतिकता का आग्रह किया था। उनका कहना था कि कोई भी संविधान लागू होने के लिए समाज में उसके लिए नैतिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। चूंकि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव और स्त्रियों के प्रति असमानता का भाव इतना गहरा है कि वहां समतामूलक नैतिकता है नहीं इसलिए इस समाज में संविधान का लागू हो पाना चुनौती है। इसीलिए उन्होंने हिंदू समाज की नैतिकता को चुनौती देते हुए 'रिडल्स इन हिंदुइज्म' जैसी पुस्तक भी लिखी। यही वजह थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया क्योंकि उनको लगता है कि बौद्ध धर्म में समानता, मैत्री और करुणा की जो भावना है वह संविधान के लिए एक नैतिक समाज निर्माण की भावभूमि तैयार करती है। इसके विपरीत महात्मा गांधी, विवेकानंद और अरविंद जैसे मनीषियों का मानना था कि हिंदू समाज में प्रवेश कर चुकी तमाम बुराइयों के बावजूद उसमें इतनी नैतिकता है कि वह समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित संविधान का पालन करेगा। वह बहुसंख्यक में होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हुए उनसे पूछकर फैसले करेगा। वह अपने समाज के विभिन्न तबकों के प्रति अपने व्यवहार को निरंतर उदार बनाता जाएगा। संघ परिवार निरंतर जिस सनातन धर्म और उसके मूल्यों की बात करता है उसके वैदिक साहित्य में मनुष्य को चार ऋणों का उत्तरदायी बताया है और उसका कर्तव्य है उन ऋणों से मुक्त होने का निरंतर प्रयास करना। इसे "मैन ड्यूंग हिज ड्यूटी" भी कहा गया है और अज्ञेय ने इसका रोचक अनुवाद 'ऋणशोध करता हुआ मध्यवर्ती मानव' के रूप में किया है। यह ऋण है --पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और भूत या मनुष्य ऋण। इसमें पहले ऋण का शोधन तो मनुष्य को परिवार के प्रति दायित्व के पालन की सीख देता है, जबकि आखिर के चार ऋणों का शोधन उसे व्यापक समाज और प्रकृति के प्रति दायित्वों से जोड़ देता है। ऋषि ऋण अपने ऋषियों से प्राप्त ज्ञान के संरक्षण और विकास की सीख देता है तो देव ऋण पूजा पाठ के बाह्य अनुष्ठान का नाम नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य भीतर के सोए हुए देवता का आह्वान है। भूत ऋण और नृऋण मनुष्य को मानव समाज की सेवा और प्रकृति सेवा की प्रेरणा देता है। नृऋण से उऋण तभी हुआ जा सकता है जब सार्वभौमिक दया भावना के साथ पूरे मानव जाति की सेवा की जाए और भूत ऋण से तब उऋण हुआ जा सकता है जब यह माना जाए कि किसी व्यक्ति का जीवन सिर्फ मानव समाज पर निर्भर नहीं करता।

उसके लिए जल, वायु, वातावरण, पशु-पक्षी, वृक्ष, वन, पहाड़, नदियों और समुद्रों का योगदान है। क्या संघ परिवार या संघ से जुड़े लोग इस कसौटी पर खरे उतरते हैं? संवैधानिक नैतिकता को तो छोड़ ही दीजिए क्या संघ परिवार ने हिंदू समाज के भीतर इस सनातन नैतिकता को भी जगाने का प्रयास किया है? दरअसल पिछले 12 सालों में संघ परिवार ने तमाम किस्म के अपराध, तमाम किस्म के भ्रष्टाचार और तमाम किस्म की अनैतिकता का सिर्फ उसी समय विरोध किया है जब वह उनके किसी विरोधी द्वारा किया गया हो। अगर वह दुष्कृत्य उनके अपने संगठन या अपनी पार्टी या अपनी सरकार से जुड़े लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे उस पर या तो खामोश रहते हैं या फिर उसका बचाव करते हैं या फिर उससे ध्यान बंटाने के लिए दूसरी बातें करने लगते हैं। वे राम का नाम तो लेते हैं लेकिन राम की मर्यादा को न तो समझते हैं और न ही उसका पालन करते हैं। उन्हें सिर्फ भौतिक संपदा चाहिए और राजनीतिक सत्ता।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कल्पना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

हरियाणा कैबिनेट ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन एक्ट, 2024 को मंजूरी दी

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज यहां जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन एक्ट, 2024 (सेंट्रल एक्ट 5 ऑफ 2024) के अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में संशोधित केंद्रीय कानून लागू करने का रास्ता साफ़ हो गया। वॉटर (प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल) संशोधित एक्ट, 2024 को संसद ने लागू किया था और 15 फरवरी, 2024 को पर्यावरण मंत्रालय वन एवं मौसम बदलाव ने नोटिफाई किया था। इस संशोधन का मकसद वॉटर (प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल) एक्ट, 1974 के तहत छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ और रैशनलाइज़ करना है, जिसका उद्देश्य भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा देना, जीवन को आसान बनाना और बिज़नेस करने में आसान बनाना है। यह बदला हुआ कानून राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन के नॉमिनेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है।

यह संशोधित एक्ट शुरू में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों पर लागू हुआ, जिन्होंने इसे अपनाने के लिए प्रस्ताव पास किए थे। दूसरे राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं से प्रस्ताव पास करके इस एक्ट को अपना सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के साथ हरियाणा अब वॉटर (प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल) संशोधित एक्ट, 2024 को अपनाने के लिए राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा, जिससे इसके नियम राज्य में लागू हो जाएंगे। बदले हुए कानून को अपनाने से पानी के प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे छोटे-मोटे प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए अपराधिक सज़ा की जगह ज़्यादा संतुलित और नियमों के पालन आधारित तरीका अपनाया जाएगा।

दयालू में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़ । (संवाददाता) हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (एच0पी0एस0एन0) की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालू-) में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। योजना में संशोधन के अनुसार दावा प्रस्तुत करने की अवधि का विस्तार तथा पूर्वव्यापी राहत देते हुए अब सभी भविष्य के दावों के लिए दावा भरने की अवधि को मृत्यु / विकलांगता की तारीख से 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करना और आज तक दायर किए गए सभी दावों के लिए 3 महीने की पूर्वव्यापी छूट (यानी मृत्यु / विकलांगता की तारीख से 6 महीने तक) की अवधि होगी। इसके साथ ही स्तरीकृत विलालम्ब क्षमा तंत्र में अब भविष्य के सभी दावों के लिए निम्नानुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ एस स्तरित विलम्ब क्षमा तंत्र होगा।

हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 को मंजूरी

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा बागवानी नर्सरी अधिनियम, 2025 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17) की धारा 22(1) के तहत हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 को मंजूरी दी गई। नए स्वीकृत हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 राज्य में बागवानी नर्सरियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक पूर्ण नियामक प्रणाली प्रदान करते हैं। ये नियम नर्सरी लाइसेंस के आवेदन, अनुदान, नवीनीकरण और श्रेणियों को जोड़ने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं। वे न्यूनतम नर्सरी मानकों, रिकॉर्ड रखने और बेची जाने वाली रोपण सामग्री के क्यूआर-आधारित प्रकटीकरण को भी परिभाषित करते हैं। यह नियम फलदार पौधों, सब्जियों, कंद, मसालों, सीज़निंग, फूलों, सजावटी पौधों, औषधीय और सुगंधित फसलों, तथा सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बागवानी पौधों के रूप में घोषित किए जाने वाले अन्य पौधों से संबंधित बागवानी नर्सरियों पर लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य प्रदेश में सभी प्रमुख बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। किसानों को अपनी किस्म के अच्छी गुणवता वाले पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पौधे बीमारी और कृमि से मुक्त होंगे। अगर विक्रेता (नर्सरी संचालक) खरीदार को खराब क्वालिटी, घटिया निम्न गुणवता वाले पौधे बेचता है, तो किसानों को खेती की लागत से दोगुना मुआवजा देने का प्रावधान है।

नियमों में नर्सरियों के नियमित निरीक्षण, लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण सहित उल्लंघन के मामले में कार्रवाई और कीटों व बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित या अवैध रोपण स्टॉक को अनिवार्य रूप से नष्ट करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक समयबद्ध अपील प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। अधिनियम को लागू करने, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने, नर्सरी संचालन में जवाबदेही बनाए रखने, पौधों के माध्यम से कीट-जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने और किसानों व खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए ये नियम अति आवश्यक हैं।

आईआईटी रोपड़ के मार्गदर्शन में एसआईईटी पंचकुला बनेगा उत्कृष्टता का नया केंद्र

(संवाददाता)

शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग हेतु ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर

चण्डीगढ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ और राज्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला ने शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाना और पारस्परिक लाभ के आधार पर छात्रों एवं संकाय सदस्यों (फैकल्टी) को वैश्विक अनुभव के अवसर प्रदान करना है। यह सहयोग अकादमिक और अनुसंधान-संचालित पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसे इंजीनियरिंग छात्रों को शीर्ष स्तर का अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। आईआईटी रोपड़ के निदेशक, प्रो. राजीव आहूजा, आईआईटी रोपड़ के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष सी. सी. रेड्डी व एसआईईटी पंचकुला के निदेशक-प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार रोज़ की बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

व्यापक छात्र विनिमय कार्यक्रम स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के छात्रों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए मेजबान संस्थान में अध्ययन या शोध करने का अवसर मिलेगा। विनिमय छात्र अपने मूल संस्थान में ही ट्यूशन और अन्य शुल्कों का भुगतान करेंगे और मेजबान संस्थान में उन्हें ट्यूशन फीस से पूरी तरह छूट दी जाएगी। दोनों संस्थानों के बीच आपसी सहमति से प्रति शैक्षणिक वर्ष प्रत्येक शैक्षणिक शाखा से छात्रों का चयन किया जा सकता है। समझौते अनुसार मेजबान संस्थान के रूप में दोनों संस्थान आने वाले विनिमय छात्रों के लिए रियायती आवास की व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेजबान संस्थान में अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को पाठ्यक्रम मिलान के बाद मूल संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकेगा। अनुसंधान करने वाले छात्रों को एक आधिकारिक प्रदर्शन मूल्यांकन और तकनीकी अनुसंधान रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। दोनों संस्थान अपने संकाय सदस्यों को सहयोगात्मक शिक्षण और अनुसंधान में शामिल होने के लिए छुट्टियों या विश्राम अवकाश (सबैटिकल लीव) के दौरान अल्पकालिक यात्राओं या निश्चित अवधि के असाइनमेंट के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान, विकास और परामर्श कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए दोनों परिसरों के संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हुए दोनों संस्थान अध्ययन सामग्री, तकनीकी साहित्य और अनुसंधान संबंधी जानकारी साझा करेंगे। समझौते के तहत संयुक्त रूप से अल्पकालिक सतत शिक्षा कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों या कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल और शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए हम हरियाणा सरकार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह, तकनीकी शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक प्रभजोत सिंह, तथा एस आ ई ई टी पंचकुला के निदेशक- प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार रोज़ का आभार करते हैं। इनके दूरदर्शी नेतृत्व, निरंतर सहयोग और तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के संकल्प के कारण ही दोनों संस्थानों के बीच यह ऐतिहासिक शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संभव हो पाया है। यह साझेदारी न केवल विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी, बल्कि हरियाणा में तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक भी स्थापित करेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी है।

लाभ में आई एचएमआरटीसी -मेट्रो यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

(संवाददाता)

नमो भारत कॉरिडोर परियोजनाओं ने भी पकड़ी रफ्तार

चंडीगढ़ । हरियाणा में एकीकृत मेट्रो और नमो भारत परिवहन नेटवर्क विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इसी क्रम में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) ने वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में उल्लेखनीय वित्तीय सुधार दर्ज करते हुए लाभ अर्जित किया है। यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव एवं एचएमआरटीसी के अध्यक्ष श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई निगम की 65वीं बोर्ड बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि जनवरी से मई 2026 के दौरान एचएमआरटीसी ने 9.18 करोड़ रुपये का अधिशेष (सरप्लस) दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में निगम को 1.98 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। निगम की कुल आय लगभग 47 फीसदी बढ़कर 35 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 23.76 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि बेहतर परिचालन प्रदर्शन और परिसंपत्तियों के प्रभावी व्यावसायिक उपयोग का परिणाम है। बैठक में बताया गया कि गैर-किराया राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले वर्ष 6.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.16 करोड़ रुपये हो गया। विज्ञापन अधिकारों की ई-नीलामी, मेट्रो परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग तथा स्टेशन आधारित गतिविधियों से प्राप्त आय में महत्वपूर्ण योगदान रहा। किराया आय में भी 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के बावजूद खर्च पर नियंत्रण बनाए रखा गया। जनवरी-मई 2026 के दौरान कुल व्यय 25.82 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 25.74 करोड़ रुपये था। परिचालन व्यय में मात्र 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रशेखर खरे ने बोर्ड को बताया कि रैपिड मेट्रो सेवा के प्रति यात्रियों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 80.76 लाख यात्रियों ने मेट्रो सेवा का उपयोग किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 73.81 लाख थी। इस प्रकार यात्री संख्या में 9.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बैठक में हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण मेट्रो और नमो भारत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रमुख परियोजनाओं में सेक्टर-56 गुरुग्राम से पंचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। लगभग 35.25 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसकी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है। बैठक में बहल्भगढ़-पलवल मेट्रो विस्तार परियोजना की भी समीक्षा की गई। लगभग 30.30 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित कॉरिडोर में 18 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़-आसौदा मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम यात्री मांग आकलन (राइडरशिप असेसमेंट) पूरा हो चुका है। नरेला-कुंडली मेट्रो विस्तार परियोजना पर जानकारी दी गई कि हरियाणा सरकार ने परियोजना के लिए 10 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे लंबे समय से लंबित इस परियोजना को महत्वपूर्ण गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर की भी समीक्षा की गई। 136.3 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 33,000 करोड़ रुपये से अधिक है। परियोजना को जन निवेश बोर्ड तथा हरियाणा सरकार की मंजूरी पहले ही प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रही मेट्रो और नमो भारत परियोजनाएं हरियाणा की दीर्घकालिक शहरी परिवहन रणनीति को नई दिशा देंगी तथा प्रदेश में सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेंगी। बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी.सी. मीणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सरवान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन को दी मंजूरी

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। यह संशोधन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 मई, 2023 को ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुपालन में किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़े नियमों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इनका उद्देश्य उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों और कैरियर प्रगति को और बेहतर बनाना है। स्वीकृत संशोधनों के तहत हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 16(1), 16(2) और 17 में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा नियमों में एक नया परिशिष्ट (एपेंडिक्स) जोड़ा गया है तथा नियमों के साथ संलग्न अनुसूची (शेड्यूल) में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना लागू की जाएगी। इसमें प्रवेश स्तर (एंट्री लेवल), चयन ग्रेड (सेलेक्शन ग्रेड) और सुपर टाइम स्केल पर कार्यरत जिला न्यायाधीशों के वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल पदों से संबंधित प्रावधानों को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियमों के अनुसार, 1 जनवरी 2020 से जिला न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से 35 प्रतिशत पद चयन ग्रेड के लिए निर्धारित होंगे। यह ग्रेड उन अधिकारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने जिला न्यायाधीश संवर्ग में लगातार कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार, जिला न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से 15 प्रतिशत पद सुपर टाइम स्केल के लिए निर्धारित होंगे। यह लाभ उन अधिकारियों को मिलेगा, जिन्होंने चयन ग्रेड में लगातार कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इसके लिए भी मेरिट और वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) की गणना 3 प्रतिशत की दर से की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की वेतन वृद्धि पिछले वर्ष के मूल वेतन के आधार पर जोड़ी जाएगी। इन संशोधनों से हरियाणा की उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को बेहतर सेवा लाभ मिलेंगे तथा न्यायिक सेवा में कैरियर उन्नति की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होगी।

75 करोड़ में तैयार होगा सीआईएसएफ का नया मुख्यालय, मंत्री ने किया 136 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। मुख्यालय के निर्माण की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने 136.03 करोड़ रुपये की लागत वाली सीआईएसएफ की कई नव-निर्मित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। सीआईएसएफ के नए मुख्यालय का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। नौ मंजिला इस अत्याधुनिक इमारत में महानिदेशक और बल की विभिन्न शाखाओं के कार्यालयों के साथ-साथ एक उन्नत नियंत्रण कक्ष, आधुनिक सम्मेलन कक्ष, विशाल सभागार, पुस्तकालय, व्यायामशाला और अन्य विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बंडी संजय कुमार ने तीन अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। * एनआईएसए, हैदराबाद में ही 20.53 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक प्रशिक्षण भवन (अभ्यास)।

*चौथी आरक्षित वाहिनी, अमरावतीपुदुर, शिवगंगा (तमिलनाडु) में 5.50 करोड़ रुपये की लागत से बने अधीनस्थ अधिकारी आवास । समारोह के दौरान, बल के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले दिवंगत सीआईएसएफ कर्मियों के आश्रित परिवारों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1-1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि के चेक सौंपे गए। इसके अलावा, बल की संगिनिका और भारतीय स्टेट बैंक की एक संयुक्त पहल के तहत, बल कर्मियों के विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को कस्टमाइज्ड मोटराइज्ड व्हीलचेयर भी प्रदान की गईं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। जवानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में आयुष्मान सीएपीएफ और कैपफिम्स के माध्यम से कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएपीएफ ई-आवास पोर्टल के जरिए पारदर्शी आवास आवंटन, और एक अत्यंत संवेदनशील विकलांगता नीति शामिल है। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों और नए खतरों से निपटने के लिए बल की मुस्तैदी का उल्लेख किया। आज के दौर में सुरक्षा चिंताएं पारंपरिक नहीं रह गई हैं, बल्कि इनमें साइबर हमले, डिजिटल तोड़फोड़, ड्रोन और तकनीक-आधारित हाइब्रिड खतरे शामिल हो चुके हैं। देश की ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने की दिशा में, सीआईएसएफ को इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड के तहत एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन का दर्जा दिया गया है, जो अब प्रमुख बंदरगाहों के सुरक्षा ऑडिट और मूल्यांकन का काम करेगा। इसके अलावा, बल ने जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च-सुरक्षा वाली जेलों का जिम्मा भी संभाल लिया है, जो आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में सीआईएसएफ की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तकनीक-आधारित सुरक्षा समाधानों पर जोर देते हुए रंजन ने बताया कि आरटीसी बहरोड़ को ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। खतरनाक ड्रोन हमलों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

भरत तिवारी मुठभेड़ पर बड़ा एक्शन, डीआईजी शाहाबाद करेंगे जांच, पांच पुलिसकर्मी निलंबित

पटना । बिहार के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सुधांशु कुमार ने सोमवार को भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुए भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले, नीट पुनर्परीक्षा में सामने आए फर्जीवाड़े और गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हुए हमले को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने बताया कि भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के लिए शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनकी कांड संख्या 169/26 और 170/26 है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच में एफएसएल समेत सभी वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। एडीजी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद एक थानाध्यक्ष, दो सब-इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि 16 जून को पहली कार्रवाई के दौरान संबंधित पुलिसकर्मी अभियुक्त को समय रहते नियंत्रित नहीं कर सके थे।

मुठभेड़ से जुड़े सवालों और कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर एडीजी ने कहा कि मामला न्यायिक जांच के अधीन है, इसलिए इस पर पुलिस की ओर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी मुठभेड़ को उपलब्धि नहीं मानती, लेकिन आत्मरक्षा की स्थिति में कानून पुलिस को आवश्यक कार्रवाई का अधिकार देता है।

उद्धव के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल

4 साल में दूसरी टूट, शिंदे बोले- छक्का लगाया; आदित्य ने पाला बदलने वालों को बिकाऊ कहा

मुंबई । महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाला बदलने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा- जब हमने विद्रोह किया था, तब शुरुआत में 40 विधायक थे और अब चौके नहीं, छक्के लग चुके हैं। 2022 में शिवसेना ने पार्टी को बचाने के लिए धनुष-बाण को बचाने के लिए विद्रोह किया था। अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों के लिए है, इन विचारों को संरक्षित करने के लिए है, इसीलिए आज इन 6 सांसदों ने बालासाहेब की असली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। शिंदे गुट में लोकसभा सांसदों की

संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। उद्धव गुट में 9 में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। सांसदों के दल-बदल पर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा- पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातोंरात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक में उद्धव गुट के 3 से 4 विधायक नहीं पहुंचे। इससे पार्टी में नई टूट की अटकलें तेज हैं। पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 288 में 20 सीटें जीती थीं। उद्धव ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया से कहा- उन्हें (बागी सांसदों को) अपना पक्ष रखने दीजिए। सही समय आने पर हम अपना पक्ष रखेंगे। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा- शिंदे ने 6 गद्दार पैदा किए हैं। हालात संभालने के लिए अब सर्जरी करनी पड़ेगी। इससे पहले संजय राउत ने एक्स पर बताया था कि उद्धव 27 जून से महाराष्ट्र में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वे बागी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे। जारी शेड्यूल के अनुसार, उद्धव 27 जून को यवतमाल, वाशिम और हिंगोली जाएंगे। 28 जून को परभणी और धाराशिव का दौरा करेंगे। 29 जून को शिर्डी पहुंचेंगे। उद्धव गुट के 6 सांसदों के बागी होने से लोकसभा में शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी। उद्धव गुट में 9 में सिर्फ 3 सांसद बचेंगे। बागी सांसदों में संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल हैं।

ट्रम्प के इशारों पर काम नहीं करता-नेतन्याहू लेबनान में इजराइली सेना हटाने से इनकार

तेहरान । इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोग यह समझते हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पर काम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यरुशलम में आयोजित एक समिट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रम्प चाहते हैं। लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। इजराइली पीएम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने-अपने हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय एक जैसी नहीं होती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जरूरत महसूस होगी तब तक इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में रहेगी।

सरकारी बाबुओं की मनमानी खत्म- दिल्ली सरकार ने 23 नई सेवाओं के लिए तय की समय सीमा

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक बेहतर कदम उठाते हुए 23 नई महत्वपूर्ण सेवाओं के डिलिवरी के लिए समय तय कर दिए हैं। अब सरकारी दफ्तरों में बाबू फाइल दबाकर महीने-दो महीने नहीं रख पाएंगे। उनको तय समय में काम करके देना होगा। सरकार ने इन सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के दायरे में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की घोषणा करते हुए साफ किया कि अब नागरिकों और कारोबारियों को लाइसेंस, एनओसी और अन्य सरकारी अनुमतियों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल का सीधा उद्देश्य सरकारी तंत्र में जवाबदेही तय करना है, जिससे आम आदमी को उसके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन को दिल्ली में धरातल पर उतारने की एक प्रभावी कोशिश है। व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाते हुए अब श्रम विभाग के तहत दुकान एवं स्थापना अधिनियम के

अंतर्गत पंजीकरण केवल एक दिन में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, फैक्टरी योजना की स्वीकृति के लिए केवल 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। व्यापारियों के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग में तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य अब अधिकतम 45 दिनों में करना अनिवार्य होगा।

इससे न केवल नए स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी, बल्कि दिल्ली में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आम जनता के लिए सीवरेज कनेक्शन अब 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नए मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर हर हाल में पूरी की जाए। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए राहत की बात यह है कि सड़क कटिंग की अनुमति 45 दिन और निर्माण सामग्री के भंडारण की स्वीकृति अब मात्र एक दिन में मिल जाएगी। साथ ही, घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए रेरा के तहत बिल्डर और एजेंट का पंजीकरण 30-30 दिनों में पूरा करना होगा। दिल्ली को पर्यटन और फिल्म शूटिंग का केंद्र बनाने के लिए अब फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर दी जाएगी।

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी- रक्षामंत्री बोले- जिस पल पानी पर खतरा लगा, हम जंग शुरू कर देंगे

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल

2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी।

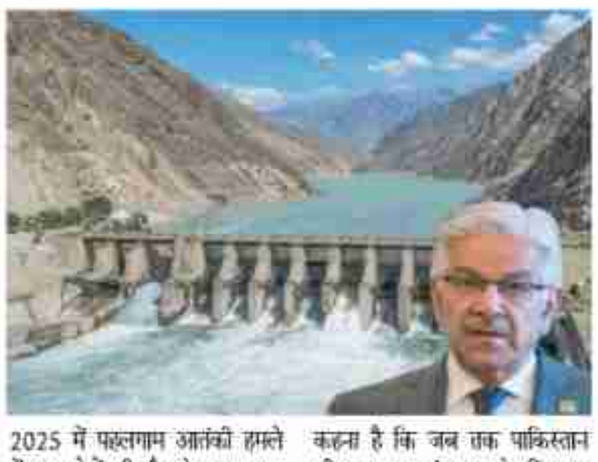

खड़ी पिकअप वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 6 मजदूरों की मौत, 21 घायल

छिंदवाड़ा ।मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया। छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे मजदूरों से भरी खड़ी एक पिकअप वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह दुर्घटना में एक महिला सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर लेमनी गांव के पास छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि दुर्घटना में एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्रीय उप पुलिस अधीक्षक रामेश्वर चौबे ने बताया कि पिकअप वैन सड़क किनारे खड़ी थी और उसका चालक किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, तभी एक ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गई। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कुछ समय तक राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाए जाने के बाद यातायात बहाल कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के दौरान ट्रक का पिछला बायां टायर फट गया, जिसके बाद वह एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार उसकी चपेट में आ गया। इसके बाद ट्रक भी पलट गया।

कतर गैस प्लांट हादसा- धमाके में 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत

दोहा। कतर में एक बेहद दुखद खबर आ रही है। यहां के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में बड़ा हादसा हुआ है। एक गैस प्लांट में अचानक भीषण धमाका हो गया। इस धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। हादसे में कुल 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के मजदूर शामिल हैं। इस भयंकर विस्फोट में 66 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन शेरीदा अल-काबी ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की है।

काम शुरू होते ही हुआ जोरदार ब्लास्ट

यह हादसा बारजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में हुआ। रविवार शाम को प्लांट में काम दोबारा शुरू

विदेश मंत्रालय और दूतावास अलर्ट

किया जा रहा था। ऑपरेशन्स के स्टार्टअप के दौरान ही अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे प्लांट में भीषण आग लग गई। कतरएनर्जी की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने तुरंत मौके पर मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जान गंवाने वाले लोग विदेशी मूल के थे। इनमें से 12 मृतक भारत के रहने वाले थे।

मदद के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन चालू

इस दर्दनाक घटना के बाद दोहा में

भारतीय दूतावास तुरंत एक्शन में आ गया है। दूतावास के अधिकारी कतर प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। भारतीय मिशन ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीड़ित परिवारों और घायलों की मदद के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। संकट की इस घड़ी में पूरा भारतीय समुदाय पीड़ित परिवारों

"कतर के बारजान गैस प्लांट में रविवार शाम को स्टार्टअप के दौरान भीषण धमाका हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 12 भारतीयों समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई और 66 लोग घायल हो गए। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ितों की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं।

के साथ खड़ा है। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है।

आपातकालीन संपर्क सूत्र

हेल्पलाइन नंबर- +974-55647502, +975-55384683

आधिकारिक ईमेल- cons.doha@mea.gov.in

घायलों का चल रहा है इलाज

हादसे में घायल सभी 66 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कतर सरकार के मुताबिक, घायलों को हर संभव बेहतरीन इलाज दिया जा रहा है। भारतीय दूतावास भी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। कतर एनर्जी ने साफ किया है कि अब प्लांट में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आगे का जांच काम शुरू कर दिया गया है।

लखनऊ की कोचिंग में आग लगने से 15 मौतें- बचने के लिए बाथरूम में छिपे, दम घुटा; 4 अफसर सस्पेंड, 3 आरोपी अरेस्ट

लखनऊ । यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 1:30 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हंटर स्टूडियो है, जिसमें 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जानकारी के मुताबिक, आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया, वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटककर नीचे उतरे। सीएम योगी ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी

योगी बोले- जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा

कर लिया गया है। मंत्री एके शर्मा ने बताया- बेसमेंट में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ, जिससे आग लगी और धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड की करीब 19 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। फायरकर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, जिससे शव निकाले हैं।

एंबुलेंस कम पड़ीं, डिप्टी सीएम पाठक रो पड़े

घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई थीं। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा- मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉमा सेंटर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। कहा- इस घटना में जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने हाई लेवल बैठक के बाद दो सदस्यीय विशेष जांच दल बनाया है। सात दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर रिपोर्ट मांगी है। एसआईटी में पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है।

आग लगने पर ऑटोमैटिक लॉक नहीं खुला

हादसे में सुखमणि (23) की मौत हो हुई है। उनके दोस्त यश ने बताया- सुखमणि 3डी एनीमेशन के ऑफिस में चार साल से नौकरी कर रहे थे। ऑफिस में करीब 40 लोग काम करते हैं। ऑफिस का मुख्य गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। आग फैलने के बाद गेट ऑटोमैटिक लॉक था। उसे खोलने में देरी हुई। जिसकी वजह से हादसा और ज्यादा गंभीर हो गया।

बताया जा रहा है इमारत वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर है। वे सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक हैं। इमारत का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। 2014 में कमर्शियल बना दिया था। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स ले रहा था। तत्कालीन अफसरों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है। 16 आरोपी हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक, इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इसलिए लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।